05112015-ls-ngp-04.qxd 11/05/2015 12:49 PM Page 1

और... एक शेर

तुम्हारे आंसुओं को सोख लेगी आग दहशत की
तुम्हें पत्थर बना देंगे, तुमें रोने नहीं देंगे
-द्विजेंद्र 'द्विज'

लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

{ बाधाओं को देखकर विचलित न हों. विश्वास रखें, जीवन में निन्यानवे द्वार बंद हो जाते हैं तब भी कोई-न-कोई एक द्वार जरूर खुला रहता है. ■ अज्ञात }

संपादकीय

भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम जरूरी

देश में एक तरफ जहां असहिष्णुता को लेकर माहौल गरमाता जा रहा है, वहीं असहिष्णुता फैलाने वाले बयान इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. ताजा मामला कर्नाटक का है, जहां भाजपा के एक नेता ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गोमांस खाने की हिम्मत करते हैं तो वह उनका सिर कलम कर देंगे. जिम्मेदार लोगों द्वारा दिए जाने वाले इस तरह के गैरजिम्मेदाराना बयान ही माहौल को खराब कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि दादरी या फरीदाबाद जैसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई हैं, महत्वपूर्ण यह होता है कि ऐसी घटनाओं के प्रति शासक वर्ग का रवैया कैसा है. अगर प्रधानमंत्री इन घटनाओं की पहले ही निंदा कर देते तो माहौल के इतना बिगड़ने की नौबत ही न आती कि अपने पुरस्कार लौटाने के लिए बुद्धिजीवियों की लाइन लग जाए. जले पर नमक यह कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं पर अमूमन खामोशी बरतते हैं वहीं सत्ता पक्ष के कुछ अन्य नेता आग में घी डालते हुए जहर उगलने वाली बयानबाजी करते रहते हैं और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती, जिससे लोगों के मन में सरकार की नीयत के प्रति संदेह पैदा होता है. कहावत है कि 'का वर्षा जब कृषि सुखाने' अर्थात समय निकल जाने के बाद समस्या के समाधान की कोशिश बहुत कारगर नहीं साबित होती. इसलिए सरकार को चाहिए कि वह आग फैलने के पहले ही उस पर काबू पाने की कोशिश करे. अगर राष्ट्रपति को सांप्रदायिक उन्माद और असहिष्णुता के खिलाफ केंद्र सरकार को एक माह में तीन बार चेताना पड़े, रिजर्व बैंक के गवर्नर को चिंता जतानी पड़े, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज को आगाह करना पड़े तो इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है. किसी भी समाज के दिशा निर्धारक उसके बुद्धिजीवी ही होते हैं, उनके विरोध को विपक्षी पार्टी के साथ संबद्ध कर देना शुतुरमुर्ग की तरह वास्तविकता से मुंह छिपाना होगा. किसी भी समाज में विभिन्न विचारधाराओं का होना स्वाभाविक बात है. चिंता तब पैदा होती है जब आपके भीतर दूसरे की विचारधारा के प्रति उग्रता पैदा हो जाए. भारत हमेशा से सहिष्णु देश रहा है. सदियों से विभिन्न विचारधाराओं को अपने भीतर समाहित कर उसने अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखा है. इसलिए आज अगर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को लग रहा है कि सहिष्णुता खतरे में पड़ रही है तो सरकार का दायित्व है कि वह उनकी चिंता का समाधान करे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि देश का विकास ही उनका लक्ष्य है. लेकिन विकास के लिए शांतिपूर्ण माहौल का होना जरूरी है. भड़काऊ बयानबाजी करने वाले नेताओं को सोचना चाहिए कि कम से कम विकास के लिए ही सही, वे वातावरण को शांत बनाए रखें. तभी प्रधानमंत्री मोदी का देश के विकास का सपना साकार हो सकेगा. ■■

श्राद्ध

आज पड़ोस की स्वर्गीय अम्माजी का श्राद्ध है. सुबह से भीड़-भाड़ दिख रही थी. पहला श्राद्ध होने से करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था. मोहल्ले की महरी आज काफी देर से काम पर आई. बर्तन साफ करते हुए बोली- ''मैडम जी, आज अम्माजी के श्राद्ध में खीर, पूड़ी, वड़ा, भजिया, पापड़, कद्दू की मसालेदार सब्जी सबकुछ उनकी पसंद का बना है पर कौए के लिए रखी गई पत्तल को खाने अभी तक कौए नहीं आए. छत पर चार कोने पर चार जगह नैवेद्य रखा है. अब जब वे (कौए) खाएं तब मेहमान खाएं!'

लघुकथा

गायत्री ठाकुर

स्वर्गीय अम्माजी से मेरी चलते-फिरते की राम-राम थी किंतु जब भी उन्हें नाखून कटवाना होता, वे बड़े विश्वास के साथ मेरे पास आ बैठतीं और मैं भी बड़े मनोयोग से उनके हाथ-पैर के नाखून काट देती. जाते-जाते ढेर सारे आशीर्वाद के साथ एक वाक्य जरूर कहती, ''ये मुएं नाखून जल्दी ही बढ़ जाते हैं.''

दोपहर के बारह बज रहे थे. अनायास ही मेरा अपनी छत पर जाना हुआ. अम्माजी की छत से हमारी छत लगी हुई है. उनकी छत पर रखे पतलों को देख पता नहीं क्यों मैंने मन ही मन कहा, ''अब आ भी जाओ अम्माजी, खाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं.''

थोड़ी ही देर में पास के नीम के पेड़ पर बैठा एक कौआ कांव-कांव करता अम्माजी की छत रखी पत्तल के पास आ बैठा और खाने लगा.

नीचे जाकर देखा तो लोग पंगत में पत्तलें लगाकर खाने के लिए बैठ रहे थे.■■

जड़ों में पानी बिना फल नहीं

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

गांव हो या शहर, पेड़ों की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचने पर फल-फूल मिलना संभव नहीं होता. यही हाल राजनीतिक दलों का है. राममनोहर लोहिया का नाम लेकर सत्ता के शिखर तक पहुंची समाजवादी पार्टी में भाइयों, बेटों-बहुओं, चाचा-भतीजों का वर्चस्व होने से जमीनी कार्यकर्ता दूर होते चले गए. इसी का नतीजा है कि इस सप्ताह उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों, 25 से अधिक मंत्रियों के परिजनों सहित अधिकांश समर्पित उम्मीदवार पराजित हो गए. यों घोषित रूप से पंचायत चुनावों में किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाते, लेकिन पिछले वर्षों के दौरान इन चुनावों में उतरे उम्मीदवारों के ताम-झाम, झंडे-डंडे, नेताओं के रिश्तेदार और प्रिय पठ्ठे जनता के सामने पेश किए जाते हैं. साधारण पंचायत की सदस्यता के लिए पच्चीस-पचास लाख का खर्च सारी आचार संहिताओं को धता बताता है. उ. प्र. सरकार के मंत्रियों और विधायकों की पत्नियों, बेटी, बेटों की हार यह साबित करती है कि छोटे गांवों तक में उनका प्रभाव नहीं रह गया. प्रभाव तभी रह सकता है, जब जीता हुआ प्रतिनिधि गांव के दुःख-दर्द, समस्याओं के निदान में कुछ सहायता करता हो. जीत के बाद गांवों-कस्बों से मुंह मोड़कर सत्ता की जोड़-तोड़, दादागीरी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाने पर भोले-भाले, गरीब, अर्द्ध शिक्षित ग्रामीण भी उनके स्वार्थ को समझ जाते हैं और मौका मिलते ही पटकनी दे देते हैं.

समाजवादी पार्टी की लाल टोपी, कांग्रेस की गांधीवादी सफेद टोपी, भाजपा की भगवा टोपी साल में दो-चार बार पार्टी के सम्मेलनों या चुनावों के समय दिखती है. किसी पार्टी दफ्तर या सार्वजनिक कार्यक्रमों में आपको ऐसी टोपी वाले नहीं दिखेंगे. स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अस्सी के दशक तक कांग्रेस पार्टी में सेवादल का अपना महत्व होता था. प्रधानमंत्री बनने से पहले राजीव गांधी को सेवा दल का मुखिया बनाया गया था. युवक कांग्रेस से निकले युवा सांसद सेवादल की कमान मिलने पर देश भर में संगठनात्मक गतिविधियां चलाते थे. लेकिन अब सेवादल का उपयोग केवल शो केस में खद्दरधारी पुतलों की तरह हो रहा है.

कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर सिद्ध हो जाएगा कि किस पार्टी की जड़ों में कितना पानी और मजबूती है.

अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी या अमित शाह के सलाहकार श्रमदान कार्यक्रमों के बजाय कम्प्यूटर, आइपॉड पर कार्यकर्ताओं की प्रोफाइल देखते हैं. सड़क-कुएं, तालाब, खेत-खलिहान का जिम्मा सरकारी मुलाजिमों पर छोड़ दिया जाता है. मुझे याद है कि उत्तर भारत के एक सुशिक्षित अनुभवी मुख्यमंत्री ने सत्ता में रहते हुए सरपंचों को पंचायत-बजट से अपनी सुख-सुविधाओं का इंतजाम करने की सलाह दी. सरपंचों की मौज हो गई. पहले सांसद-विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर भी सामान्य जनता अपने मुखिया के कहने पर कांग्रेस को वोट दे देती थी. लेकिन जब उसे समझ में आया कि गांव का मुखिया पंचायत के धन से अपना ही मकान बना रहा या बेटों के लिए मोटरसाइकिल-ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो उसने सरपंच-मुखिया की सुनना भी बंद कर दिया. इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की पंचायतों, नगर-पालिकाओं, नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस इक्का-दुक्का सीट जीत पा रही है. वह भी स्थानीय उम्मीदवारों के बल पर. श्रमदान, बिजली-पानी के लिए आंदोलन की बात दूर रही सेवादल के शिविर तक नहीं लगते.

कांग्रेस का विकल्प बनने वाली भाजपा अब दस करोड़ की सदस्यता का दावा करने लगी है. भाजपा के अधिकांश नेता-कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शिक्षा-दीक्षा लेकर राजनीतिक अखाड़े में पहुंचे हैं. नागपुर, दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ, पटना और मुंबई तक में सरसंघचालक गुरु गोलवलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को हमने सामान्य स्वयंसेवकों के साथ एक पंक्ति में बैठकर खाना खाते और कई मुद्दों पर खुली असहमति और सहमति के दृश्य देखे हैं. लेकिन क्या अब संघ-भाजपा का कार्यकर्ता अमित शाह के सामने असहमति के साथ मुंह खोल सकता है? इंदिरा गांधी से अटल बिहारी वाजपेयी तक के प्रधानमंत्री कार्यालय में साधारण कार्यकर्ता सुबह के दर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर अपना दुखड़ा या क्षेत्र की समस्या सुना सकता था. लेकिन अब तो भाजपा अध्यक्ष से मिलने के लिए सांसदों-विधायकों और मुख्यमंत्रियों तक को लंबा इंतजार करना होता है. वे पंक्तिबद्ध अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर बैठते हैं. नाम पुकारे बिना अध्यक्ष के कमरे में झांकने की 'हिमाकत' करने पर 'अध्यक्षजी' की कड़ी फटकार सुनने को मिलती है. तभी तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार बुरी तरह पराजित हो गए.

कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर सिद्ध हो जाएगा कि किस पार्टी की जड़ों में कितना पानी और मजबूती है. ■■

मुशर्रफ और आतंकवाद

नजरिया उर्दू प्रेस का

■ राजश्री यादव

उर्दू मीडिया ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने संबंधी दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद अफसोसनाक बताया है.

जो आतंकवादी इस्लाम की छवि बिगाड़ने की लगातार कोशिश करते रहे, वो जनरल मुशर्रफ के हीरो थे.

'सहाफत डेली मुंबई' ने लिखा है, यह बात अक्सर विभिन्न मौकों पर अखबारों में छपती रही है कि पाकिस्तान के शासक खासतौर पर फौजी शासक दहशतगर्दों और उनसे जुड़े संगठनों के लिए अपने दिल में न सिर्फ सहानुभूति रखते हैं, बल्कि उनकी हौसलाअफजाई भी करते रहते हैं, ताकि वो भारत में आतंकी गतिविधियां करें. अब इस बात की पुष्टि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के उस बयान से होती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 1990 की दहाई में लश्कर जैसे आतंकी संगठन का समर्थन किया और उसे प्रशिक्षित किया. मुशर्रफ ने ये भी स्वीकारा कि ओसामा बिन लादेन और अलजवाहिरी जैसे आतंकी नेता पाकिस्तान के हीरो थे लेकिन बाद में वो विलेन बन गए. अखबार ने लिखा है ये किस कदर अफसोस की बात है कि जो आतंकवादी इस्लाम की छवि बिगाड़ने की लगातार कोशिश करते रहे, वो पाकिस्तान खासतौर से जनरल मुशर्रफ के हीरो थे.

छोटी-छोटी मासूम बच्चियों से बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं के मद्देनजर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इन घटनाओं के मुजरिमों को नामर्द बना दिए जाने के सुझाव का स्वागत करते हुए श्रीनगर से प्रकाशित **'डेली रौशनी'** ने लिखा है, मासूम बच्चियों की इज्जत लूटने वाले दरिंदों को अगर नामर्द बना दिया जाए, तो ऐसी सजा से उनकी जिंदगी जहन्नुम बनकर रह जाएगी और वो किसी बच्ची को तो दूर, किसी भी औरत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे.

नई दिल्ली से प्रकाशित डेली **'हमारा मकसद'** ने लिखा है, बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बहस बिहार से लेकर दिल्ली तक जारी है और उसके साथ ही ये बहस भी जारी है कि अगर भाषण देने में माहिर पीएम मोदी बिहार में वो जादुई करिश्मा न दिखा पाए, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाया था तो भाजपा का क्या होगा. दिल्ली में ये बहस चल रही थी कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर किसी वजह से भाजपा हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे छोड़े जाएंगे और जश्न मनाया जाएगा. तो क्या अमित शाह को लगने लगा है कि बिहार में महागठबंधन के मुकाबले में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की हालत पतली है. ये अंदेशा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अगर किसी को अपनी कामयाबी का पूरा-पूरा यकीन था तो वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी थे. ■■

और अंत में ....

अब ये नेकी भी हमें जुर्म नजर आती है/ सबके ऐबों को छिपाया बहुत दिन हमने. (साभार- इन्कलाब डेली)

क्लिक

स्कॉटलैंड के डुम्बरटन में मिलटन के नजदीक ओवरटुन पुल पर कुत्ते आत्महत्या कर लेते हैं. 1859 में बना यह पुल लगातार कुत्तों द्वारा आत्महत्या करने के बाद से सुर्खियों में है. हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कुत्ते यहीं आकर ऐसा क्यों करते हैं.

बच्चों को दें सरदार पटेल के योगदान की जानकारी

गौरीशंकर राजहंस
पूर्व सांसद एवं पूर्व राजदूत

सरदार पटेल गांधीजी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे. जब भारत आजाद हुआ तब उनको उपप्रधानमंत्री बनाया गया जबकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने. दोनों की टीम ठीकठाक ही चल रही थी. 1950 में सरदार पटेल का असमय निधन हो गया. उसके बाद तो ऐसा लगा मानो वे देश के इतिहास के पन्नों से गायब होते चले गए. सरदार पटेल ने भारत को एक बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उसे नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं.

अंग्रेजों ने बड़ी अनिच्छा से भारत को दो मुल्कों में बांटकर विदाई ली. उस समय देश में सैकड़ों रजवाड़े थे. तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने कहा कि जिस भी राजे-रजवाड़े की इच्छा हो वह या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में. नतीजतन अनेक छोटे- छोटे राज्यों के रजवाड़े चोरी छिपे पाकिस्तान से समझौता करने लगे और पाकिस्तान में मिलने का प्रयास करने लगे. सरदार पटेल ने एक झटके में उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और कह दिया कि वे समझौता संधि पर तत्काल दस्तखत करें और भारत में सम्मिलित हो जाएं. लाचार होकर सैकड़ों राजे-रजवाड़ों को भारत में अपनी रियासत का विलय करना पड़ा. यदि सरदार पटेल नहीं होते तो भारत में पता नहीं कितने छोटे-छोटे राज्य होते और जाने कितने और पाकिस्तान भारत की भूमि पर पैदा होते.

जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन ने भ्रमित किया कि यदि वे कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ले जाएं तो पश्चिम के सभी देश खासकर इंग्लैंड और अमेरिका भारत की भरपूर मदद करेंगे और वे पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे. इसी गलतफहमी में पंडित नेहरू कश्मीर के मामले को सुरक्षा परिषद ले गए. इस सिलसिले में वे ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट करना चाहते थे कि कश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद में जाएगा और वहां 'जनमत संग्रह' होगा जिससे लोगों के विचार जाने जाएंगे कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं. सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को बहुत समझाया कि ऐसा मत कीजिए. हमने कबाइलियों को कश्मीर से मार भगाया है. कश्मीर रियासत के मालिक महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं अब किसी तीसरे पक्ष के दखल देने का सवाल कहां उठता है? परंतु पंडित नेहरू नहीं माने.

कम लोगों को यह मालूम है कि सरदार पटेल ने एक लंबा पत्र लिखकर पंडित नेहरू को चेताया था कि वे चीन पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करें. क्योंकि चीन एक विस्तारवादी देश है. वह कभी भारत का मित्र नहीं हो सकता है.

आवश्यकता है कि नई पीढ़ी के बच्चों को सरदार पटेल की जीवनी और उनके संघर्ष के बारे में स्कूलों में विस्तार से पढ़ाया जाए.

कुछ वर्ष पहले भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने मुझे बताया था कि एक बार सरदार पटेल के लड़के बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए. वे दिल्ली आकर अपना इलाज कराना चाहते थे. सरदार ने अत्यंत बेरुखी से कहा यह सरकारी बंगला है. इसे मैं परिवार वालों की सेवा में नहीं लगा सकता. उस उद्योगपति ने मुझे कहा तब हम ही लोगों ने अपने घर में सरदार पटेल के लड़के को मुंबई में रखकर लंबे अरसे तक इलाज कराया. दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया. परंतु यह यही दिखाता है कि सरदार पटेल अपने सिद्धांत के कितने पक्के थे.

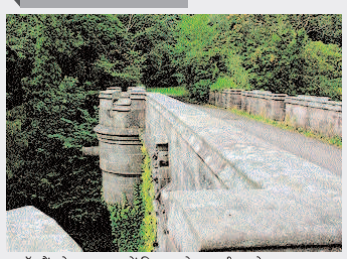

यह दुर्भाग्य की बात है कि सेकेंडरी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में न तो सुभाषचंद्र बोस की जीवनी पढ़ाई जाती है और न सरदार पटेल की. आवश्यकता है कि नई पीढ़ी के बच्चों को सरदार पटेल की जीवनी और उनके संघर्ष के बारे में स्कूलों में विस्तार से पढ़ाया जाए. ■■

चीन से होनी चाहिए ब्रह्मपुत्र पर बातचीत

भारत भूषण
जाने माने पत्रकार

यारलंग-शांगपो नदी तिब्बत से गुजरती है. इस पर चीन जांगमू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति चीन सरकार ने हाल ही में दी है. तिब्बत में यह अपने किस्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा. लेकिन इसकी वजह से भारत, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और असम में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. नई दिल्ली को पिछले पांच वर्ष से इस बात की जानकारी थी कि बीजिंग की यारलंग-शांगपो पर हाइड्रो पावर विकसित करने की योजना है, जबकि अन्य प्रोजेक्ट जैसे डागू, जियाचा व जीझू योजना व निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और इनसे भी भारत के लिए कई किस्म की समस्याएं हैं.

विभिन्न सीमाओं से गुजरने वाली यारलंग-शांगपो (भारत में ब्रह्मपुत्र) नदी व्यवस्था पर जो भारत व चीन के बीच राजनयिक वार्ता है, वह अधिकतर शक के बादलों से ही घिरी रहती है, खासकर इसलिए कि इस साझा नदी व्यवस्था पर जानकारी व डाटा को आपस में बांटने का अभाव है. दोनों सरकारों के बीच जो ब्रह्मपुत्र पर द्विपक्षीय बातचीत या आदान-प्रदान होता है, वह नौकरशाही की गोपनीयता में ढका रहता है और फिर उस पर 1962 के भारत-चीन युद्ध और अरुणाचल प्रदेश पर जो एक-दूसरे की दावेदारी है, वह भारी पड़ जाती है. इन कारणों के चलते ब्रह्मपुत्र के पानी के बंटवारे को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है जिसकी वजह से भारत के किसानों को ज्यादा परेशानी है.

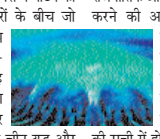

दरअसल, अब समय आ गया है कि दोनों- भारत व चीन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की घोषणाओं से आगे बढ़ें और ब्रह्मपुत्र जलक्षेत्र (बेसिन) के समक्ष जो बड़े मुद्दे हैं उनको संबोधित करें और बहुआयामी प्रोजेक्ट्स में निवेश करें. समझने की बात यह है कि वर्तमान में ऊर्जा के नदी तटीय संबंध बहुत अधिक असंतुलित व गैर बराबरी वाले हैं. उन्हें राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से संबोधित करने की आवश्यकता है, खासकर ब्रह्मपुत्र के मामले में, जहां दोनों देश क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी हैं, जबकि सह-नदी तटीय देश बांग्लादेश व भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची में होने के नाते कुछ ज्यादा ही पिस रहे हैं.

भारत और चीन के लिए इसलिए आवश्यक है कि ब्रह्मपुत्र पर विचार-विमर्श का कोई फ्रेमवर्क तैयार करें ताकि वार्ता व समझौता हो सके. वार्ता में सभी बिंदु शामिल होने चाहिए, उसमें सभी स्टेट होल्डर्स या दावेदारों के लिए उचित मंच होना चाहिए और इसके अतिरिक्त साझा समस्या को संबोधित करने के लिए नए रास्तों की पहचान करना भी जरूरी है. ट्रैक तीन व ट्रैक दो स्तर की बातचीत प्रक्रिया में यह क्षमता है कि दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्क के अवसर उपलब्ध होंगे, अविश्वास का जो माहौल है उसमें कमी आएगी और समाधान के सिलसिले में जिस तरह से भारतीय व चीनी बात करते हैं, सोचते हैं व चाहते हैं उसमें भी बदलाव आ सकेगा.

निकट भविष्य में औपचारिक समझौता तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन विकल्पों पर गौर अवश्य किया जा सकता है कि किस तरह नई दिल्ली व बीजिंग वैकल्पिक प्रक्रियाओं पर विचार करके ब्रह्मपुत्र पर भविष्य के समझौतों की तरफ बढ़ सकते हैं. बातचीत की प्रक्रिया इस बात की जमीन तैयार कर सकती है कि सहमति व असहमति के बिंदु क्या हैं और साथ ही वर्तमान के जो डर हैं कि 'पानी चुराया जा रहा है' या दूसरे को कठिनाई में डालने के लिए बांध बनाए जा रहे हैं, को भी दूर किया जा सकता है. बातचीत उन चिंताओं को संबोधित करे जो नदी तटीय देशों के लोगों को सता रही हैं. ■■

तोल बोल

कांग्रेस ने तो 16 मई 2014 को ही जनादेश स्वीकार कर लिया था. मगर इसके बाद देश में विचारधारा की लड़ाई हुई है और कांग्रेस इसे लड़ती रहेगी.
■ **आनंद शर्मा**, कांग्रेस नेता

मेरे लिए 5 नवंबर का दिन खास है, क्योंकि मैं भारत में पहली बार टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहा हूं. यह मेरा जन्मदिन भी है तो रोमांच दोगुना हो गया है.
■ **विराट कोहली**, कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम

इतिहास पर नजर 5 नवंबर

आज ही के दिन 1978 में दो दिनों के दंगों के बाद ईरान के प्रधानमंत्री जाफर शरीफ इमामी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था. ईरान के शाह ने शरीफ इमामी को दो माह पहले ही नियुक्त किया था. इमामी का ताल्लुक शिया समुदाय से था. शाह ने उनकी नियुक्ति देश में जारी दंगों के मद्देनजर की थी. ये दंगे खासतौर पर विश्वविद्यालयों में हो रहे थे. लेकिन नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का हंगामों पर कोई असर नहीं हुआ. देश भर में जारी हंगामे शाह की धर्मनिरपेक्षता की योजना के विरोध में थे. शाह ने देश की सत्ता 1941 में संभाली थी. हंगामों के कारण देश में मार्शल कानून लगा दिया गया था. ■■

■1556-पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया.
1630-स्पेन और इंग्लैंड के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर.
1725-स्पेन और आस्ट्रिया ने गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किया.
1811-स्पेन के खिलाफ मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष.
1854-क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस की संयुक्त सेना ने इकेरमान में रूसी सेना को पराजित किया.
1870-बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक राजनीतिज्ञ चित्तरंजन दास का जन्म.
1920-इंडियन रेडक्रास सोसाइटी की स्थापना.
1961-भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू अमेरिका की यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे.

पाठकों के पत्र

तुअर दाल की बिक्री

सरकार ने दाल की जमाखोरी करने वाले कालाबाजारियों के गोदामों में छापे मारकर पूरे देश में हजारों टन तुअर दाल जब्त की है. यह जब्त की गई दाल तुरंत जनता को सस्ते दामों में बेची जाए. गुजरात में 120 रुपए प्रति किलो तथा आंध्र व तेलंगाना सरकार तुअर दाल की बिक्री सब्सिडी वाली दर यानी 50 रुपए किलो पर राशन दुकानों के जरिए कर रही है. फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं ऐसा हो सकता. सरकार से निवेदन है कि सरकारी बिक्री केंद्र खोलकर अथवा राशन दुकानों के जरिए सभी कार्डधारकों को कम से कम कीमत में यह दाल बिक्री कर आम जनता को राहत पहुंचाए.
■एस.एस. सिंह, नागपुर

साहित्य दिशा देता है

हिंदी की अनदेखी करने से देश का या आम आदमी का विकास नहीं हो सकता. हिंदी एवं हिंदी के साहित्यकारों का अपमान करना निंदनीय है, क्योंकि साहित्य ही समाज को दिशा देने का काम करता है.
■पी.बी. पराडकर 'ललित' छिंदवाड़ा

कला पारखी

एक बनिए की बाजार में छोटी सी मगर बहुत पुरानी कपड़े सीने की दुकान थी. उसकी इकलौती सिलाई मशीन के बगल में एक बिल्ली बैठी एक पुराने गंदे कटोरे में दूध पी रही थी. एक बहुत बड़ा कला पारखी दुकान के सामने से गुजरा. कला पारखी होने के कारण जान गया कि कटोरा एक एंटीक आइटम है और कला के बाजार में बढ़िया कीमत में बिकेगा. लेकिन वह ये नहीं चाहता था कि बनिए को इस बात का पता लगे कि उसके पास मौजूद वह गंदा सा पुराना कटोरा इतना कीमती है.

हास्य

उसने दिमाग लगाया और बनिए से बोला, लालाजी नमस्ते, आपकी बिल्ली बहुत प्यारी है, मुझे पसंद आ गई है. क्या आप बिल्ली मुझे देंगे? चाहे जो कीमत ले लीजिए.

बनिए ने पहले तो इनकार किया मगर जब कलापारखी कीमत बढ़ाते-बढ़ाते दस हजार रुपयों तक पहुंच गया तो लालाजी बिल्ली बेचने को राजी हो गए और दाम चुकाकर कला पारखी बिल्ली लेकर जाने लगा.

अचानक वह रुका और पलटकर बनिए से बोला- 'लालाजी, बिल्ली तो आपने बेच दी. अब इस पुराने कटोरे का आप क्या करोगे? इसे भी मुझे ही दे दीजिए. बिल्ली को दूध पिलाने के काम आएगा. चाहे तो इसके भी 100-50 रुपए ले लीजिए.

बनिए ने जवाब दिया, 'नहीं साहब, कटोरा तो मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि इसी कटोरे की वजह से आज तक मैं 50 बिल्लियां बेच चुका हूं.' ■■

gñWmnH$ gnmXH$: nd. Odmhabmb XSm
M`a_Z, E[SQm{a`b ~mS : {dO` XSm
E{SQa-BZ-Mr\$: amOD XSm
gnmXH : {dH$mg {_l★
★ nr. Ama. ~r. H$mZZ H$ AZgma gnU gnmXH$` Xm{`Ed H$ {bE {Oå_Xma.
© लोकमत समाचार _ àH$m{eV g^r gm_Jr H$m gdm{YH$ma bmH$_V _r{S>`m àm`dQ> {b. H$ nmg gm{jV h. bmH$_V _r{S>`m àm`dQ> {b. H$ {bE _ÐH$ Ed àHmeH बालाजी मुले Ûmam bmH$_V _r{S>`m àm. {b., ßbmQ> H$. 192, 207, 208 E_. AmB. Sr. gr. BYS{ñQ´>`b E[a`m, ~Qr~mar, ZmJna _{ÐV Ed bmH$_V ^dZ n. Odmhabmb Zhê _mJ, ZmJna _ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 bmBÝg) \$ÚS>g : 6618555
Email : gnmXH$s` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com